which has now come down to 12.20 lakh tonnes only, annually. because of the negligence of MMTC and less number of ships calling at Paradip to export ore. The Central Government should take immediate steps to clear this backlog of 3.1 million tonnes at the Port and should ensure regular export of 40 lakh tonnes of iron-ore annually, so that thousands of Adivasi workers who earn their livelihood by working in the mines get regular work and the economy of the State is not shattered.

(v) NEED TO PROVIDE ADEQUATE FACILITIES TO WEAKER SECTIONS OF THE SOCIETY BY THE BANKS.

श्री महाबीर प्रसाद (बांसगांव) : मान्यवर, आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान उत्तर प्रदेश में या देश के अन्य भागों में बैंकों द्वारा दी जा रही सुविधाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, इन बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों, जन जातियों, स्वतंत्रता सेनानियों या अन्य कमजोर वर्गों को स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, आई० आर० डी०, एस० एफ० डी० ए०, एन० आर० ई० पी० या अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, उस से काफी लोग लाभान्वित हो रहे हैं और होने वाले भी हैं। लेकिन खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक उन गरीबों को दी जा रही सुविधाओं में लगातार बाधक बन रहे हैं। उदाहरण के लिए मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बांसगांव में मेरे ही गृह विकास खंड गगहा में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की यह दशा है कि सारी अर्हताओं को पूरा करने के बाद भी लगभग 6 माह तक उन गरीबों को उस बैंक की तरफ किराया-भाड़ा लगा कर दौड़ना पड़ता है। यही हालत प्रत्येक विकास खंडों खंडों की है। इसके बाद कहीं जाकर उन गरीबों को ऋण या अनुदान प्राप्त हो पाता है। जबकि ये सभी बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और उनकी नीति है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में हरिजनों, गिरिजनों तथा कमजोर वर्गों की दशा को सुधारने के लिए काम करेंगे। किन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। फलस्वरूप हमारी सरकार की जो समाजवादी एंव प्रगतिशील नीति है उसे सही ढंग से उन ग्रामीण अंचलों में नहीं पहुंचाया जा रहा है।

अतः वित्त मंत्री महोदय से सादर अनुरोध है कि वे सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से कहें कि वे बैंक हमारी प्रगतिशील नीति को सफल बनाने के लिए कम से कम समय में उन गरीबों को ऋण या अनुदान की रकम दें।

(vi) RECONSIDERATION BY GOVERNMENT OF THE PROPOSED TOUR OF INDIAN CRICKET TEAM TO BRITAIN.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Mormugao): The recent decision by some of Britain's leading cricketeers to offer their services to South Africa in exchange for substantial payment raises the question whether the Indian cricket team should go ahead with their proposed our of Britain this summer or call it off. The issue cannot be evaded by the Board of Control. Many professionals who do not deserve to be called sportsmen have been regularly coaching South African players and taking part in league matches. To such people, money is more important than holding allofit the banner of human right or UN resolutions on the subject. The news about the tour of British cricketeers to South Africa has been accompanied by another item about a Register drawn up by the UN's Special Committee against Apartheid which reveals that more than 360 sportsmen from 29 countries have taken part in